to (d) After deregulation of pricing and distribution of iron and steel w.e.f. 16/1/ 1992, Government has no role to play in pricing of steel produced by main producers. Secondary producers were free to fix their own prices even prior to this date.

The last revision of price by Steel Authority of India Limited was effected on 01/8/1996 when the average increase in price of representative categories of steel ranged from Rs. 200 to Rs. 700 per tonne. Visakhapatanam Steel Plant revised its prices last w.e.f. 9/8/96, with increase in ex-plant prices of 3% to 12% per tonne on various products. According to Tata Iron and Steel Company Limited, their list of prices are revised twice a year.

Major determinants in pricing of steel products are input costs, prevalent market conditions such as demand and availability, ability to export at remunerative prices, etc.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिल मालिकों के लिए निर्धारित गेहूं और चावल व्यापारियों को दिया जाना

2479. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्यालय तथा राज्यों स्थित स्थानीय कार्यालयों से गेहूं और चावल की आपूर्ति मिल मालिकों को करने के बजाय व्यापारियों को कर दी गई है जिसके कारण जुलाई और अगस्त के महीने में मैदा और आटा महंगा हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन निर्णयों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोखिम में डाले बिना खाद्यान्नों के बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के उद्देश्य से थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, रोलर फ्लोर मिलों, चक्कियों, सहकारी समितियों, सुपर बाजार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों आदि सहित सभी को गेहूं की बिक्री करता है। भारतीय खाद्य निगम ने जुलाई-अगस्त, 1996 का दौरान खुले बाजार में 5.18 लाख टन गेहूं और 0.56 लाख टन चावल की बिक्री की थी। मैदा और आटा जैसे गेहूं के उत्पादों के मूल्य फ्लोर मिलिंग उद्योग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा गेहूं की खुली बिक्री में की गई कथित अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रमाणनीय शिकायतों की जांच की गई थी। इस जांच के परिणामस्वरूप, श्रेणी-1 के 3 अधिकारियों और श्रेणी-3 के 4 कर्मचारियों को प्रमुख दंड के रूप में चार्जशीट जारी की गई थी। श्रेणी-1 के एक अधिकारी, श्रेणी-2 के एक अधिकारी और श्रेणी-3 के तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। श्रेणी-1 के एक अधिकारी और श्रेणी -2 के एक अधिकरी, जो भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए थे, को असंवेदनशील पदों पर स्थानांतरित किया गया था।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-2 के दो और श्रेणी-3 के 2 कर्मचारियों को पुलिश द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भी एक आर०सी०संख्या 45/96-सी०एच०डी० गहन जांच करने के लिए दर्ज की है।

Controversy between SAIL and CIL over coal price hike

2480. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether any unsavory controversy

is raging between SAIL and CIL over hike in coal price, as reported in the Hindustan Times, dated the 29th October, 1990; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?;

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) No, Sir. Steel Authority of India Ltd. have expressed their financial difficulties to CIL on the revision of coal prices w.e.f. 20.10.96. SAIL have urged CIL for improving the quality of coal supplies.

The prices of Coking coal and A,B and C grades of non-coking coal have been increased by CIL w.e.f. 20.10.96 to compensate for the increase in the costs of inputs, which are beyond the control of the Coal India Limited.

Outcome of the World Food Summit Held in Rome

2481. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the World Food Summit held in Rome in November this year was attended by the Prime Minister;

(b) the main observations and recommendations made therein and the decisions taken for mutual food cooperation in case of natural calamities and disasters;

(c) whether right to access to food and nutrition was recognised by the World Conference as a Human Right; and

(d) the steps being taken by Government in pursuance thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The Summit adopted what is called the Rome declaration with specified objectives and plans and programmes of action. It includes efforts to prevent and prepare for natural disasters and man-made emergencies and to meet transitory and emergency food requirements in ways that encourage recovery, rehabilitation, development and a capacity to satisfy future needs.

(c) The Rome declaration on World Food Security reaffirms the right of everyone to have access to safe and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger.

(d) Most of the programmes and plan of action identified in the Rome declaration are already an imporatnt part of the plans and policies pursued by various Departments of the Government. Further discussions are taking place to evolve a suitable mechanism for implementing the action plans & programmes incorporated in the Rome declaration.

भारत-रूस व्यापार को बढ़ावा दिया जाना

2482. श्री गोविन्दराम मिरीः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत-रूस व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;